and except in regard to matters of policy where it shall be bound to act in conformity with and in implementation of such policy decision of the Government of India.

2. Role of the State Government/U.T. Admns.

The State Government shall maintain a list of children's homes and adoption agencies working in the State. They shall also form an Advisory Committee on adoption to effectively supervise the adoption work and to carry-out the inspection of the adoption agencies.

3. Role of Recognised Indian agencies for adoption

The placement agencies shall make all out efforts to place a child in an Indian family according to a time-frme. The Voluntary Coordinating Agencies shall issue necessary clearance certificate in favour of a placement agency for pursuing inter-country adoption only if they fail to find an Indian family for the adoptive child.

4. Recognition of Indian Agencies

The State Government shall submit its recommendation on the application of renewal submitted by the placement agencies to the Central Adoption Resource Agency within a period of two months from the date of receipt of the applications. In the absence of any re-commendation from the State Government within the time frame, the concurrence of the State Government will be presumed by the Central Adoption Resource Agency and the application will be processed by Central Adoption Resource Agency for grant of recognition within maximum period of two months. If no response is received from the Central Adoption Resource Agency to the appli-cation by the placement agency within a further maximum period of two months or before the expiry of the recognition of the agency whichever is later, the renewal shall be deemed to have been granted for a period of two years.

5. Enlistment of Foreign agencies for adoption

(i) The request from the foreign agencies for the enlistment for the purpose of inter-country adoption shall be routed through the Indian Eimbassies/High Commission in their country. The recommendation of the Indian Embassies/High Commissions in their country will be taken into account while considering the request of the foreign agencies for enlistment by the Central Adoption Resource Agency.

6. Role of Voluntary Coordination Agencies

A time period for 60 days instead of 30 days shall be given to V.C.A. for putting their best efforts to place the child within the country and in case they fail they shall issue necessary clearance certificate to the placement agencies within a max- imum period of 60 days.

7. Role of Scrutinising Agencies

The Court may appoint any agency, being a body of experts in the field of child care and welfare not in itself involved in any manner in the placement of children in adoption as a scrutinising agency. The court shall have the power to appoint any other scrutinising agency recognised by CARA depending upon the situation.

8. Miscellaneous

It will be desirable for the Governemnt of India to enter into bilateral agreement with countries which are receiving chil- dren from India for the purpose of adop- tion and such bilateral agreements should provide for full coordination between the appropriate authorities of India and the receiving State and also for protection and safeguarding of the welfare of the children taken for adoption in the receiv-ing State.

जाति प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना

4407. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रह रहे अन्य राज्यों के पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण जारी करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा 8 अप्रैल, 1994 को जारी अनुदेशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एफ०सं० 12011/11/94-बी०सी०सी०

कल्याण मंत्रालय
(बी०सी०सी०)
नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल, 1994

सेवा में,

विषय:-अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से आकर बसे व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी किया जाना।

महोदय,

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 नवम्बर, 1993 के पत्र संख्या 36012 / 22 / 93 स्थापना (एस०सी० टी०) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को सूचित किया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जिन्होंने रोजगार, शिक्षा इत्यादि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में शरण ली है, उस राज्य से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिस राज्य को छोड़कर वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 नवम्बर, 1993 के पत्र सं० 36012 / 22 / 93-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुसार किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का निर्धारित प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जो अन्य राज्य से आया हुआ प्रवासी हो, अन्य पिछड़े वर्ग का प्रणाम पर जारी कर सकता है बशर्ते कि वह उसके पिता के जन्म स्थान वाले राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता को जारी किया गया वास्तविक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। लेकिन उन मामलों को छोड़कर जिनमें निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता हो कि प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से पूर्व मूल राज्य से विस्तृत जांच करवाया जाना जरूरी है।

2. प्रमाण पत्र इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना जारी किया जाएगा कि क्या संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया गया है, जिस राज्य को छोड़कर उसने अन्य राज्य में शरण ली है। यह सुविधा व्यक्ति के अन्य पिछड़े वर्ग के दर्जे को किसी एक राज्य अथवा अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के मामले में नहीं बदलती। अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में प्रवास करने पर, जहां जाति अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में नहीं शामिल हो, अपने मूल राज्य तथा केन्द्र-सरकार से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमत्व रियायतें / लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा लेकिन उस राज्य से नहीं जहां उसने प्रवास किया हो।

3. अनुरोध है कि सभी सक्षम प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाए कि वे प्रमाण पत्र की सत्यता से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 15 नवम्बर, 1993 के परिपत्र के अनुरूप शक्ति सम्पन्न सक्षम प्राधिकारियों की सूचियों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। किसी अन्य प्राधिकारी को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

भवदीय,

(एम० एस० पंडित)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

PAPERS LAID ON THE TABLE

12.00 NOON

Report of the National Human Rights Commission, New Delhi

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): Madam I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the period from October, 1993 to March, 1994, under sub-section (2) of section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

[Placed in Library. *See* No. LT 6391/84]

(ii) Memorandum of Action Taken on the above Report.

[Placed in Library. See No. LT 6392/84]

I. Report and Accounts (1992-93) of the Air India Limited, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1991-92) of the National Airports Authority, New Delhi and related papers.

III. Report (1992-93) of the Commission of Railway Safety, Lucknow.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY PARLIAMENTARY AFFAIRS SMT. MARGARAT ALVA: on behalf of (SHRI